

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कोटा-बूंदी में नया ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- अंडमान तथा निकोबार बेसिन में तेल और गैस अन्वेषण के लिए खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति-एक्स के अंतर्गत चार ब्लॉक आवंटित किए हैं।
- रंगत खाड़ी में पुलिस ने मछुआरों को बचाया।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री श्रीनरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतनी महत्वपूर्ण यात्रा करने के बाद, व्यक्ति को एक बदलाव महसूस होना चाहिए और उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि अंतरिक्ष यात्री इस परिवर्तन को कैसे समझते और अनुभव करते हैं। प्रधानमंत्री के जवाब में, शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष का वातावरण बिल्कुल अलग होता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण का अभाव एक प्रमुख कारक है। प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या यात्रा के दौरान बैठने की व्यवस्था एक जैसी रहती है। श्री शुक्ला ने कहा – हाँ, यह एक जैसी ही रहती है। श्री मोदी ने आगे बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों को एक ही सेटअप में तेईस-चौबीस घंटे बिताने पड़ते हैं। शुक्ला ने इसकी पुष्टि की और कहा कि अंतरिक्ष में पहुँचने के बाद, अंतरिक्ष यात्री अपनी सीटें और हार्नेस खोल सकते हैं, और कैप्सूल के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या कैप्सूल में पर्याप्त जगह है। शुभांशु शुक्ला ने जवाब दिया कि हालाँकि यह बहुत विशाल नहीं था, फिर भी कुछ जगह उपलब्ध थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैप्सूल लड़ाकू विमान के कॉकपिट से भी ज़्यादा आरामदायक लग रहा था। शुक्ला ने पुष्टि करते हुए कहा कि हाँ यह उससे भी बेहतर है।

<><><><><><><>

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज एक हजार पांच सौ सात करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राजस्थान के कोटा-बूंदी में नया ग्रीन फील्ड



देते हुए उन्होंने कहा कि यह अभियान अठारह अक्टूबर तक चलेगा। इसके साथ ही सरकार वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

<><><><><><><><>

सरकार अण्डमान तथा निकोबार बेसिन में कच्चे तेल और हाइड्रोकार्बन भंडारों का पता लगाने के लिए लगातार उपाय कर रही है जिससे देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दिया जा सके और आयात निर्भरता को कम किया जा सके। सरकार ने हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति की शुरुआत के बाद अण्डमान तथा निकोबार बेसिन में तेल और गैस अन्वेषण के लिए खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति – एक्स के अंतर्गत चार ब्लॉक आवंटित किए हैं। इन ब्लॉकों में अब तक तीन कुओं की खुदाई की जा चुकी है। भारत के हाइड्रोकार्बन संसाधन आकलन अध्ययन में अण्डमान तथा निकोबार बेसिन में तीन सौ इक्विवलेंट मिलियन मीट्रिक टन तेल के बराबर के हाइड्रोकार्बन संसाधनों का अनुमान लगाया गया है। ए.एन. बेसिन, अण्डमान तथा निकोबार बेसिन के चौराहे पर स्थित है, जो बंगाल-अराकान तलछटी प्रणाली का हिस्सा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

<><><><><><><><>

अमेरिका के व्यापारिक नियमों से समुद्री निर्यात प्रभावित नहीं : सरकार मत्स्यपालन राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने बताया कि अमेरिका द्वारा लगाए गए स्वच्छता व स्थिरता संबंधी नियम केवल भारत पर नहीं, कई देशों पर लागू हैं। आंध्रप्रदेश सहित भारत के समुद्री खाद्य निर्यात पर प्रभाव उत्पाद की गुणवत्ता, मांग और समझौतों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सी-रेंजिंग, आर्टिफिशियल रीफ्स और संरक्षण उपायों से मछुआरों की आजीविका सुरक्षित करने और निर्यात प्रतिस्पर्धा बनाए रखने पर काम कर रही है।

<><><><><><><><>

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बिस्वजीत बसु और न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता पच्चीस अगस्त से आठ सितम्बर तक पोर्ट ब्लेयर सर्किट कोर्ट में मामलों की सुनवाई करेंगे।

<><><><><><><><>

